



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042020-219064
CG-DL-E-16042020-219064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]
No. 98]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020/चैत्र 27, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2020/CHAITRA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

(मामला सं. एम टी आर-02/2020

विषय : रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलीट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत

फा. सं. 07/10/2020-डीजीटीआर.—

- मै. गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें रूस (जिसे यहां आगे ‘संबद्ध देश’ भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलीट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयातों से संबंधित मध्यावधिक समीक्षा जांच के लिए अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पिछली की गई जांच के समय से परिस्थितियां बदल गई हैं और परिस्थितियों में ऐसे बदलाव से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है और उसने मध्यावधि समीक्षा हेतु तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

क. पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 13 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना सं. 21/1/1998 द्वारा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलीट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाले अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और दिनांक 30 दिसंबर, 1999 की अधिसूचना सं. 141/99-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर केन्द्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
4. प्राधिकारी ने 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी जिसे पहली निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में दिनांक 18 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 110/2004-सीमाशुल्क द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।
5. प्राधिकारी ने दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 15/30/2008-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी जिसे दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में दिनांक 3 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 57/2010-सीमाशुल्क के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।
6. प्राधिकारी ने तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/2/2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था और दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/2017 द्वारा आगे संशोधित किया गया था। छूटी 5 जून 2021 तक लागू रहेगा।

ख. विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में यथापरिभाषित रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलीट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) (जिसे आगे “पी टी एफ ई” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) है।
8. पी टी एफ ई को विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है जैसे मोलिंडिंग ग्रेड, फाइन पाउडर, एक्वस डिसपर्सन और फील्ड ग्रेडों के यौगिक ग्रेड। सभी ग्रेड जिन्हें पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान शुल्क के दायरे में शामिल किया गया था, वर्तमान समीक्षा के दायरे के भीतर आते हैं। पी टी एफ ई को प्राथमिक रूप से उसकी अद्वितीय विशेषताओं के लिए इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक, मेकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ये विशेषताएं हैं रासायनिक निष्क्रियता, इलैक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन, घर्षण का कम गुणांक, नाँून टॉक्सिक, अज्वलनशील, विकीरण के प्रतिरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण का कम स्तर और व्यापक आवर्ती रेंज के दौरान उत्कृष्ट विद्युतीय विशेषताएं हैं।
9. पी टी एफ ई को अधिनियम के अंतर्गत उप शीर्ष सं. 390461 तथा उप शीर्ष सं. 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग

11. आवेदन मेसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में एक प्रमुख निर्माता है, जो भारत में विषय वस्तुओं के कुल उत्पादन का 99% से अधिक का लेखा-जोखा रखता है। आवेदक ने दावा किया है कि यह विषय के किसी भी निर्यातक या निर्माता से संबंधित देश में या भारत में पीयूसी या पीयूआई के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है। दूसरी कंपनी, जिसका नाम है, हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड, जो विषय वस्तुओं का उत्पादन भी करती है, कुल उत्पादन का 1% से कम उत्पादन होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि नियमों के नियम 2 (बी) और नियम 5 (3) के संदर्भ में घरेलू उद्योग की ओर से 'आवेदन' या उसके द्वारा किया गया है।

ड. समीक्षा के लिए आधार

12. आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के पाठन में मात्रा और मार्जिन दोनों की दृष्टि से वृद्धि हुई, निम्नलिखित विवरण के अनुसार मात्रा और मार्जिन दोनों के संदर्भ में:-
- क. रूसी उत्पादक पहले केवल एक उत्पाद प्रकार (4 आर बी), का निर्यात कर रहे थे परंतु अब अनेक उत्पाद किस्मों का निर्यात कर रहे हैं।
 - ख. कच्ची सामग्री की लागत में भारी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में वृद्धि हो गई है।
 - ग. यहां तक कि जब उत्पाद की उत्पादन लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गई है, फिर भी रूस के उत्पादक ने अपनी कीमतों में अनुपातिक वृद्धि नहीं की है।
 - घ. आयातों की मात्रा में 2018-19 तक गिरावट आई थी परंतु वर्तमान अवधि में इनमें कीमतों में भारी गिरावट के साथ अत्यधिक वृद्धि हो गई है।

13. आवेदक ने दावा किया है कि परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन और पाठन मार्जिन में वृद्धि हो गई है। आवेदक ने दावा किया है कि मौजूदा उपाय बढ़े हुए पाठन के कारण हो रही क्षति का निवारण करने में अब पर्याप्त नहीं रह गए हैं। आवेदक ने एक बार फिर घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाने वाली परिस्थितियों में बदलाव प्रदर्शित करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

च. जांच शुरूआत

14. आवेदक के विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन के आधार पर और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पहले से लागू पाठनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की जरूरत को सिद्ध करते हुए प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली नियम 23 (1 क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा रूस से संबद्ध वस्तु पर पहले से बढ़ाए गए पाठनरोधी शुल्क की राशि को बढ़ाने की जरूरत की जांच करने के लिए मध्यावधिक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

15. चूंकि यह जांच एक मध्यावधि समीक्षा है, इसलिए संबद्ध देश का दायरा मूल जांच में संबद्ध देश तक सीमित है अर्थात् यह रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरुद्ध है।

ज. जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 (9 महीने) की है और क्षति अवधि में अप्रैल, 2016 – मार्च 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाठनरोधी शुल्क जून, 2021 तक लागू है, जांच की अवधि 9 महीने अर्थात् दिसंबर, 2019 तक भी रखी गई है ताकि एस एस आर जांच, यदि आवश्यक हो, को समय पर शुरू और पूरा किया जा सके।

झ. प्रक्रिया

17. इस समीक्षा में रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाली दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/2/2015 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे।
18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।
21. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

ठ. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी को भेजी जाए तथा वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को पहुंच जानी चाहिए। तथापि, यह भी नोट किया जाए कि उक्त उप नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली तारीख अथवा निर्यातक देश के उचित कूटनीतिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में सस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/सत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा :-
- (i) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
 - (ii) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हाई कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिण्यतियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्वक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

Case No. MTR-02/2020**Subject : Initiation of Mid-term Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in or exported from Russia.****F. No. 07/10/2020-DGTR.—**

1. M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), for Midterm Review investigation concerning imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from Russia (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The Applicant has alleged that the circumstances have changed from the time of last conducted investigation on imports of product under consideration from the subject country and such change in circumstances has led to continued material injury to the domestic industry and has requested for midterm review and enhancement of the antidumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Background

3. The Designated Authority notified final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Polytetrafluoroethylene (PTFE) *vide* Notification Number 21/1/1998 dated 13th October, 1999, originating in or exported from Russia and definitive anti-dumping duty was imposed, by the Central Government, on the subject goods *vide* Customs Notification No. 141/99-Customs dated 30th December 1999.
4. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duties *vide* Notification No. 15/6/2003-DGAD dated the 7th October, 2004 which was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 110/ 2004-Customs dated 18th November, 2004, pursuant to first sunset review investigation.
5. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duties *vide* Notification No. 15/30/2008-DGAD dated the 26th February, 2010 which was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 57/2010-Customs dated 3rd May, 2010, pursuant to second sunset review investigation.
6. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duties *vide* Notification No.15/2/2015-dated 12th April, 2016 which was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 23/2016-Customs dated 6th June, 2016 and further amended by Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017, pursuant to third sunset review investigation. The duties are in force till 5th June 2021.

B. Product under Consideration

7. The product under consideration in the present investigation, as defined in the last conducted sunset review investigation is “Polytetrafluoroethylene” (also referred to as PTFE) originating in or exported from Russia.
8. PTFE is produced in various grades, such as moulding grade, fine powder, aqueous dispersion and compound grades of filled grades. All grades that were included in the scope of the previous investigation and current duties are within the scope of the present review. PTFE is primarily used in

electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

9. PTFE is classified under subheading no 390461 and at subheading no. 39046100 under the Act. Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations.

C. Like Article

10. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the product under consideration manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic Industry

11. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. The Applicant is a major producer in India accounting for more than 99% of the total production of the subject goods in India. The Applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC or PUI in India. The other company, namely, Hindustan Fluorocarbons Ltd., which also produces the subject goods has production less than 1% of the total production. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Grounds for Review

12. The Applicant has claimed that dumping in the product under consideration has intensified – both in terms of volume and margin as per the following details:-
 - a. Whereas the Russian producer was earlier exporting only one product type (4RB), it is now exporting a number of product types.
 - b. There has been significant increase in the cost of raw materials leading to increase in the non-injurious price of the domestic industry.
 - c. Even when the cost of production of the product has increased substantially, the producer from Russia has not increased its prices proportionately.
 - d. The volume of imports declined till 2018-19, but has significantly increased in the current period with significant fall in prices.
13. The Applicant has claimed that resultantly, the injury margin and dumping margin has increased. The Applicant has claimed that the existing measure is no longer sufficient to address the injury being caused by increased dumping. The Applicant has furnished *prima facie* evidence, showing change in circumstances leading to further material injury to the domestic industry.

F. Initiation

14. On the basis of a duly substantiated application of the Applicant, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence substantiating the need for a mid-term review of the anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from Russia, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1A) of the Rules, the Authority hereby initiates a mid-term review investigation to examine the need for enhancement in the quantum of the anti-dumping duty earlier extended on subject goods from Russia.

G. Subject Country

15. Since the investigation is a midterm review investigation, the scope of the subject country is confined to the subject country in the original investigation *i.e.* against the subject goods originating in or exported from Russia.

H. Period of Investigation

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019- December 2019 (9 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI. Keeping in view that the AD duty is in existence till June 2021, the period of investigation has been considered as 9 months i.e. till December 2019 only.

I. Procedure:

17. The review will cover all aspects of the final findings published *vide* Notification No. 15/2/2015-dated 12th April, 2016, recommending imposition of antidumping duty on imports of subject goods from the subject country.
18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. Submission of Information

19. The exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
21. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

K. Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/sessions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority